मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, बैरागढ़, भोपाल

बनाम

सुधाकर और अन्य

15 अप्रैल, 1977

[वी. आर. कृष्णा अय्यर और ए. सी. गुप्ता, जेजे.]

उचित भविष्यवाणी, का सिद्धांत- मोटर वाहन अधिनियम, 1939, धारा 110ख- मुआवजे देना- एक बच्चे की मृत्यु और एक दुर्घटना में कमाने वाली पत्नी की भी मृत्यु- दावेदार पति पत्नी की आय पर निर्भर नहीं है और 11 महीने के भीतर पुनर्विवाह करता है- नुकसान का आंकलन उचित भविष्यवाणी घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, धारा 1ए के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

बस दुर्घटना- पीड़ित लड़का जिसकी उम्र लगभग चार साल है एक संपन्न परिवार से आता है- दाहिने टिबिया और टखने के जोड़ के पास निचले तीसरे हिस्से के फैबुला के यौगिक फ्रैक्चर से अक्षम- उच्च न्यायालय द्वारा हर्जाने के रूप में 20,000 की वृद्धि उचित है- मोटर वाहन अधिनियम, 1939, धारा 110ख।

23 जून, 1961 को एक बस दुर्घटना में श्रीमती उषा कोटस्थाने और उनके एक साल के बेटे की मृत्यु हो गई। एक संपन्न परिवार से आने वाला लगभग चार साल का लड़का शैलेश कुमार टखने के जोड़ के पास अपने दाहिने टिबिया और निचले तीसरे हिस्से के फैबुला के यौगिक फ्रैक्चर के कारण विकलांग हो गया था। सुधाकर कोटास्थाने, मृतक के पति और 1968 की सी. ए. 2254 में प्रतिवादी संख्या 1 और श्रीमती. शैलेश कुमार की माँ और 1968 की सी. ए. 2255 में प्रतिवादी संख्या 1 इंदु

बाला भंडारी ने मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, ग्वालियर में आवेदन किया। न्यायाधिकरण ने (i) सुधाकर की पत्नी की मृत्यु, जिसके परिणामस्वरूप घर में असुविधा, पीड़ा, सदमा, अव्यवस्था और लगभग 11 महीने की अवधि के लिए जीवन की स्थिति पैदा हुई, यानी जब तक कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया, और (ii) इस तथ्य पर विचार किया कि श्रीमती उषा एक स्कूल में शारीरिक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थीं, जिनका वेतन रु 190/- 150-10-250 रुपये के पैमाने में था और रुपये की राशि से सम्मानित किया। मृतक की कमाई पर 75,000/- के दावे के बदले मुआवजे के रूप में 15, 000/- रुपये की गणना की गई। न्यायाधिकरण ने भी 10, 000/- नुकसान के रूप में और रु 890/- श्रीमती इन्दुबाला को विशेष क्षति के रूप में राशि का आदेश दिया। प्रत्यर्थियों और अपीलार्थी दोनों ने न्यायाधिकरण के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने मुआवजे को सुधाकर के मामले में 50,000/- और इंदुबाला के मामले में 20,000/- बढ़ा दिया।

1968 के सी. ए. सं. 2254 में अपील को स्वीकार करते हुए और 1968 के सी. ए. सं. 2255 में अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

(1) इंग्लैंड में आम तौर पर नुकसान का आंकलन करने की एक विधि वार्षिक आधार पर शुद्ध आर्थिक नुकसान की गणना करना और "वार्षिक 'निर्भरता' की राशि के रूप में मूल्यांकन किए गए आंकड़े को वर्ष की खरीद की संख्या से गुणा करके कुल पुरस्कार पर पहुंचना है", यानी, उन वर्षों की संख्या जो गुणक या गुणक को तय करने में अभेद्य कारकों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक चलने की उम्मीद थी। पति भले ही पत्नी की आय पर निर्भर न हो, लेकिन पत्नी की मृत्यु के लिए पति को देय नुकसान का आंकलन करने का आधार समान होगा। [631 एबी]

मैलेट बनाम मैक मोंगले 1970 (ए. सी.) एच. एल. 166 में नियम को 174 पर अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया।

पी. बी. कादर बनाम थचम्मा ए. आई. आर. 1970 केरल 241, अनुमोदित।

नुकसान का आंकलन करने में कुछ अन्य कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जैसे कि जीवन की अनिश्चितताओं और त्वरित भुगतान के तथ्य-कि पति को एकमुश्त भुगतान मिल रहा होगा, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए उसे कई वर्षों में ड्रिबलेट में उपलब्ध होना चाहिए था। अनिश्चितताओं के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए और तदनुसार कुल आंकड़ा कम किया जाना चाहिए। हो सकता है कि मृतक किसी न किसी कारण से सेवानिवृत्ति की आयु तक कमाई करने में सक्षम न रहा हो, जैसे कि बीमारी या परिवार की देखभाल के लिए अधिक समय बिताना, जिसके बढ़ने की उम्मीद थी। इस प्रकार, इन अभेद्य कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राशि को कम करना होगा। [630 जी-एच]

तत्काल मामले में, मृतक की मृत्यु के समय उसके सामने 35 साल की सेवा थी। दावेदार का नुकसान यथोचित रूप से रु 50/- प्रति माह अर्थात रु 600/- प्रति वर्ष। सभी प्रासंगिक कारकों और आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए और 20 को उपयुक्त गुणक के रूप में लेते हुए, यह आंकड़ा रु 12, 000 आता है। इसलिए, न्यायाधिकरण के निर्णय को बहुत कम के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि यह उचित आधारों पर आधारित नहीं था। उच्च न्यायालय भी नुकसान का अनुमान 50, 000/- रुपये तक लगाने में सही नहीं था, जिस तरह से उसने किया। [631 बीसी]

हालाँकि, तत्काल मामले में, शल्य चिकित्सा द्वारा विकृति को दूर करने की संभावना थी जब लड़का 16 साल का हो गया था, लेकिन "स्थायी लंगड़ा होने की

संभावना" की दूसरी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, सामान्य नुकसान को बढ़ाकर रु 20, 000/-, तत्काल मामले में, रु 890/- विशेष क्षति के रूप में उचित है। [631 डी-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1968 की सिविल अपील सं. 2254 और 2255

विविध पहली अपील सं. 12/64 मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 10-1-1967 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

राम पंजवानी, रामेश्वर नाथ, दोनों अपीलों में अपीलार्थी की ओर से।

ए. जी. रत्नपर्खी, सीए 2254/68 में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

एस. के. गंभीर, सीए नंबर 2255/68 में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया-

गुप्ता जे.

23 जून, 1961 को अपीलार्थी के स्वामित्व वाली एक बस, जो ग्वालियर से इंदौर जा रही थी, एक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके परिणामस्वरूप दो यात्रियों, लगभग 23 वर्ष की श्रीमती उषा कोटस्थाने और उनके एक वर्ष के बेटे की मृत्यु हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक शैलेश कुमार था, जो लगभग चार साल का लड़का था। मुआवजे के दावे ग्वालियर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए गए थे। श्रीमती उषा कोटस्थाने और उनके बच्चे की मृत्यु के मुआवजे के लिए उनके पति श्री सुधाकर कोटस्थाने ने आवेदन किया था और नाबालिग शैलेश कुमार की चोट के संबंध में दावा उनकी ओर से उनकी अभिभावक माँ श्रीमती इंदुबाला भंडारी ने किया था। सुधाकर कोटस्थाने और इंदुबाला भंडारी भी एक ही

बस में यात्रा कर रहे थे और दोनों को चोटें आईं और उन्हें न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा दिया गया, लेकिन ये अपील उनके मामलों या कोटस्थाने के मृत बच्चे के संबंध में दावे से संबंधित नहीं हैं। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कहने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर हमारे समक्ष दो अपीलें, श्रीमती उषा कोटस्थान की मृत्यु और शैलेश कुमार को लगी चोट के संबंध में दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए हर्जाने की मात्रा को बढ़ाने वाले उच्च न्यायालय के सामान्य फैसले के खिलाफ हैं। 1968 का सी. ए. 2254 श्रीमती कोटस्थाने के मामले में और 1968 का सी. ए. 2255 शैलेश कुमार के मामले में निर्णय से संबंधित है।

श्रीमती उषा कोटस्थाने की मृत्यु के संबंध में, दावा न्यायाधिकरण ने उनके पति सुधाकर को हर्जाने के रूप में 15000/- रुपये का फैसला सुनाया। अपनी मृत्यु के समय वह इंदौर के एक स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थीं, जिनका वेतन 150-10-250 रुपये के ग्रेड में रु 190/- प्रति माह था। माना जाता है कि सुधाकर ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के एक साल के भीतर फिर से शादी कर ली। न्यायाधिकरण ने दावे से इस तरह निपटाः

> "वर्तमान मामले में यह पत्नी की मौत का मामला है। पति अपनी पत्नी की कमाई पर निर्भर नहीं था। वह खुद स्वतंत्र रूप से कमाई कर रहे थे। आवेदक ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसकी पूर्व पत्नी की मृत्यु के कारण, वह उसकी आय से वंचित रहा है, न ही वह उस पर निर्भर था। यह सच है कि आवेदक की पत्नी शिक्षित, स्वस्थ, नियोजित और कमाई करने वाली थी। जहाँ तक साहचर्य के नुकसान का सवाल है, यह फिर से सच है कि उन्हें लगभग 11 महीने तक इस नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने दूसरी

बार शादी की। गैर-आवेदक द्वारा इस बिंदु पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है कि दूसरी पत्नी उतनी ही निपुण, शिक्षित और स्वस्थ है जितनी पूर्व पत्नी थी। आवेदक की पत्नी की मृत्यु ने उसे मानसिक सदमा, दर्द और उसके घर में असुविधाजनक स्थिति पैदा की होगी। घर में वह काम जो वह अपनी पत्नी से घर की देखभाल के लिए ले सकता था, वह भी 11 महीने की इस अवधि के दौरान आवेदक के लिए उपलब्ध नहीं था। गोद में एक बच्चे के साथ स्थापित वैवाहिक जीवन का लाभ भी इस दौरान आवेदक को खो दिया गया था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के पक्ष में, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी पत्नी की मृत्यु के 11 महीने बाद उसकी फिर से शादी हो गई थी, मुझे लगता है कि मुआवजे के रूप में रु 15000/-, उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 11 महीने की अवधि के लिए असुविधा की स्थिति, घर में सदमे और जीवन का सामना करना पड़ा।"

सुधाकर कोटस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम दोनों ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय निम्नलिखित रूप में आगे बढ़ा। "उनके कमाई जीवन की अवधि" को 35 वर्ष के रूप में गिना गया था जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु के रूप में 58 वर्ष लगने थे। दुर्घटना की तारीख से पहले छह वर्षों के लिए, उच्च न्यायालय ने औसत मासिक आय के रूप में रुपये 200/- और शेष उनतीस वर्षों की सेवा के लिए प्रति माह औसत आय रु 250/- फिक्स किया। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने उनकी कुल कमाई की गणना रु 96, 000/- तक की। अपने स्वयं के खर्चों के लिए भत्ता देते हुए और पदोन्नति और इसके परिणामस्वरूप अर्जित वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सोचा

कि वह इस राशि का आधा हिस्सा परिवार के लिए "आसानी से फैला" सकती थी और मृत्यु के कारण आय के नुकसान का अनुमान रुपये 50, 000/- लगाया। उच्च न्यायालय ने तदनुसार मुआवजे को बढ़ा दिया। सुधाकर की दूसरी शादी के बारे में उच्च न्यायालय ने कहाः

> "लेकिन फिर भी, दूसरी शादी को पहली शादी का विकल्प नहीं कहा जा सकता है। दूसरी पत्नी परिवार की कमाने वाली सदस्य नहीं है और न ही यह दिखाया गया है कि सुधाकर को दूसरी शादी से किसी भी तरह से आर्थिक रूप से लाभ हुआ है। इसलिए दूसरी शादी के बावजूद वित्तीय नुकसान होगा।"

इन निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय ने सुधाकर कोटस्थाने द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

ऊपर उद्धृत न्यायाधिकरण के आदेश के उद्धरण से पता चलता है कि मुआवजे की मात्रा तय करने में न्यायाधिकरण इस धारणा में था कि आवेदक ने अपनी पत्नी की मृत्यु के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान के आधार पर कोई दावा नहीं किया था। इसमें न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से गलत था। दावा याचिका के पैराग्राफ 11 में, रु 75,000- मुआवजे के रूप में दावा किया जाता है और पैराग्राफ यह स्पष्ट करता है कि राशि की गणना मृतक की अपेक्षित आय पर की जाती है। यदि ऐसा कोई दावा नहीं होता तो न्यायाधिकरण को 15000/- रुपये का निर्णय देना शायद ही उचित होता। केवल 11 महीने की अवधि के लिए आवेदक को हुए मानसिक सदमे और असुविधा के लिए हर्जाने के रूप में, जिसके बाद उसने पुनर्विवाह किया। उच्च न्यायालय भी 50, 000/- रुपये के नुकसान का अनुमान लगाने में सही नहीं लगता है। जिस तरह से उसने किया। क्या

मृतक का औसत मासिक वेतन रु 200/- या 250/-रु माना जाता है। हमें इस बात से सहमत होना मुश्किल लगता है कि उस राशि का केवल आधा ही उसके मासिक खर्चों के लिए पर्याप्त होता जब तक कि वह सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो जाती, ताकि शेष आधे को उसके पति के मासिक नुकसान के उपाय के रूप में लिया जा सके। यह असंभव नहीं है कि उसने अपने वेतन का आधा हिस्सा घर में योगदान दिया होगा, लेकिन फिर यह मान लेना उचित होगा कि जो पति थोड़ा अधिक वेतन पर काम करता था, उसने अपने हिस्से का योगदान साझा पूल में किया होगा जिसका उपयोग दोनों के रहने सहने के लिए किया जाता। इसलिए हमें नहीं लगता कि यह मान लेना सही है कि पति का नुकसान मासिक वेतन का आधा था जो मृतक को उसके सेवानिवृत्त होने तक मिलने की संभावना थी। यदि सामान्य पूल के लिए हर महीने औसतन उन्होंने रु 100/- दिये, तो उसका नुकसान लगभग 50/- रु प्रति माह से अधिक नहीं होगा और यह मानते हुए कि उन्होंने 58 वर्ष की आयु तक काम किया, कुल नुकसान रु 19,000/- से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन नुकसान का आंकलन करते समय कुछ अन्य कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्हें उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि जीवन की अनिश्चितताएं और त्वरित भुगतान का तथ्य-कि पति को एकमुश्त भुगतान मिल रहा होगा, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए उसे कई वर्षों से ड्रिबलेट में उपलब्ध होना चाहिए था। अनिश्चितताओं के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए और तदनुसार कुल आंकड़ा कम किया जाना चाहिए। मृतक शायद किसी न किसी कारण से सेवानिवृत्ति की आयु तक कमाई नहीं कर पाए होंगे, जैसे कि बीमारी या परिवार की देखभाल के लिए अधिक समय बिताना, जिसके बढ़ने की उम्मीद थी। अतः इन अभेद्य कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राशि को कम करना होगा। नुकसान का आंकलन करने में अनुमान का कुछ तत्व अपरिहार्य है; मैलेट बनाम मैक मोनागल, 1970 (ए. सी.) (एच. एल.) 166 (174) में लॉर्ड पीयर्स, इसे "उचित भविष्यवाणी"

कहता है। सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त 15000/- रुपये एक उचित आंकड़ा प्रतीत होता है जिसे हम परेशान करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

नुकसान का आंकलन करने की एक विधि, जो आमतौर पर इंग्लैंड में अपनाई जाती है, जैसा कि मैलेट बनाम मैक मोनागल (उपरोक्त) से प्रतीत होता है, वार्षिक आधार पर शुद्ध आर्थिक नुकसान की गणना करना और "वार्षिक" निर्भरता "की राशि के रूप में मूल्यांकन किए गए आंकड़े को" वर्ष की खरीद "की संख्या से गुणा करके कुल निर्णय पर पहुंचना है, (पृष्ठ 178) अर्थात, लाभ कितने वर्षों तक चलने की उम्मीद थी, गुणक या गुणक को तय करने में अभेद्य कारकों को ध्यान में रखते हुए। पति भले ही पत्नी की आय पर निर्भर न हो, लेकिन पत्नी की मृत्यु के लिए पति को देय नुकसान का आंकलन करने का आधार समान होगा। यहाँ, महिला के सामने 35 साल की सेवा थी जब उनकी मृत्यु हो गई। हमने पाया है कि दावेदार का नुकसान उचित रूप से रु 50/- प्रति माह अर्थात रु. 600/- प्रति वर्ष है। सभी प्रासंगिक तथ्यों और आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए और 20 को उपयुक्त गुणक के रूप में लेते हुए, यह आंकड़ा रु 12,000/- आता है। इसलिए न्यायाधिकरण के निर्णय को बहुत कम के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि यह उचित आधार पर आधारित नहीं था। अपीलार्थी (पी. बी. कादर बनाम थचम्माः ए. आई. आर. 1970 केरल 241) द्वारा केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए, जिसमें हममें से एक पक्षकार था, मुआवजे का आंकलन करने का वही तरीका अपनाया गया था।

दूसरी अपील (1968 की सी. ए. संख्या 2255) लगभग चार साल की उम्र के एक लड़के को लगी चोट से संबंधित है। घाव के संक्रमण के साथ उन्हें टखने के जोड़ के पास अपने दाहिने टिबिया और निचले तीसरे हिस्से के फैबुला में फ्रैक्चर का सामना

करना पड़ा। स्किन-ग्राफ्टिंग करनी पड़ी और लड़के को 25 जून, 1961 से 4 अगस्त, 1961 तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसकी जाँच करने वाले डॉक्टर के अनुसार, बच्चे के स्थायी रूप से लंगड़ा होने की संभावना थी, जिसके लिए 16 साल या उससे अधिक उम्र में एक और ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी मामले में, डॉक्टर की राय में विकृति निश्चित रूप से तब तक बनी रहेगी जब तक कि लड़का 16 साल का नहीं हो जाता, जब एक और ऑपरेशन से इसे हटाया जा सकता है। ट्रीबुनल ने सामान्य नुकसान को 10,000/- और विशेष नुकसान को 890/- रुपये कर दिया। उच्च न्यायालय ने सामान्य नुकसान को बढ़ाकर 20,000/- रुपये कर दिया। साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि लड़का एक संपन्न परिवार से आता है। हालाँकि इस बात की संभावना थी कि जब वह 16 साल के हो गए तो शल्य चिकित्सा द्वारा विकृति को दूर किया जा सकता था, लेकिन दूसरी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

परिणाम में, 1968 की अपील सं 2254 की अनुमति है, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण के फैसले को बहाल कर दिया जाता है; 1968 की अपील संख्या 2255 खारिज कर दी जाती है। किसी भी अपील में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस. आर.

1968 के सी. ए. 2254 की अनुमति दी गई।

1968 का सी. ए. 2255 खारिज कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक कैलाश पूनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।